TRANSITION ERA

Editor : *RESHU SHANKER*
Sub-Editor : *Sachchidanand Yadav*

ट्रांजिशन एरा

The Weekly English & Hindi

ISSUE-38 ***VOL -07*** **THURSDAY, 22-09-2022** **RNI Regn. No. ANDBIL/2016/70294** ***Rs. 5.00***

Admn committed towards provision of basic minimum amenities and last mile connectivity to the geographically separated villages: CS

Mayabunder, Sep 21:

A&N Administration is committed towards the welfare of the Islanders and it will leave no stone unturned to resolve the issues and aspirations of the people of North & Middle Andaman region. Genuine issues/demands highlighted by the people of the area, will be attended to on priority for its time bound redressal, said the Chief Secretary, A&N Administration, Shri Keshav Chandra,IAS during an interaction meeting held with the PRIs and Head of Offices in the Panchayat Hall, Pokadera, Mayabunder.

The Chief Secretary, who is currently on his third day visit to N&M Andaman District, took note of the grievances pertaining to various sectors which were highlighted by PRIs from different Gram Panchayats of Mayabunder area.

Opening the sectoral discussions, the Chief Secretary emphasized the need to understand the geographical disadvantages, limitations of funds, shortage of manpower and technical capabilities of executing agencies. He explained that nation-wide there is shortage of manpower including Andamans, which cannot be

contd. at page-5

DC (SA) holds meeting with stakeholders for retail sale of crackers

Port Blair, Sep 20:

Keeping in view the forthcoming festive seasons starting from the month of October and in view of the constraints, safety aspects, cleanliness of business premises and also to prevent import and sale of banned fireworks, the Deputy Commissioner, South Andaman

contd. at page-6

Hindi Noting & Drafting Competition organized

Port Blair, Sep 21: As part of various programmes being organised during Hindi Fortnight-2022, a Hindi Noting & Drafting Competition was conducted for the Gazetted Officer of A&N Administration today in the Mini Conference Hall of Secretariat. Officers of various Department/Offices participated in this competition.

As part of the series of programmes being organised in connection with Hindi Fortnight-2022, a Hindi Workshop for Nodal Officer (Official Language) and one dealing staff (Hindi) will be held tomorrow (Sept. 22) at 10 am in the Conference Hall, Secretariat, Port Blair for various Department/ Offices of A&N Administration. On this occasion, Shri Vishwendra, Secretary (OL), A & N Administration will be the chief guest.

Training on Waste Management in Agri. & Allied Sector gets underway

Port Blair, Sept. 20

The Secretary (Agri), A&N Administration, Shri Pankaj Kumar, IAS inaugurated a four days off Campus training programme on 'Waste Management in Agri.& Allied Sectors' for the officers of Agriculture and allied Departments of A&N Islands today in the Conference Hall of Directorate of Agriculture, Haddo. The programme is being organized by Extension Education Institute, PJTSU, Hyderabad in association with Department of Agriculture, A&N Administration. Speaking on the occasion, the Secretary (Agri.) motivated the participants to participate actively and acquire the scientific knowledge through agricultural waste management training programme, for its effective implementation in the field. Since agriculture is on a large scale, the agricultural wastes generated cannot be ignored and proper care has to be taken to decompose it through the agricultural waste management programme.

The Joint Director (Agri.), HQ, Dr (Smti) Chanda Srivastava stressed upon the need of such training for extension functionaries of scheme implementing Departments while Dr I. Sreenivasa Rao, Senior Professor, EEI briefed about the course contents of the training & insisted for transfer of knowledge & skills learned for the benefit of farming community. Dr. R. Vasantha, Professor, EEI proposed the vote of thanks.

Altogether, 30 officers from Agriculture & Allied Departments i.e. Department of Animal Husbandry & Veterinary Services, Fisheries and Rural Development are participating in the training programme, a press release from Directorate of Agriculture said.

EPS pensioners asked to submit 'Jeevan Pramaan Patra' digitally to get pension

Port Blair, Sep 21: All EPS pensioners have to submit annual Jeevan Pramaan Patra for getting pension. The Life Certificate thus submitted is valid for one year, and the pension shall be stopped only if it has not been submitted after one year. Hence, all pensioners have been requested to submit Jeevan Pramaan Patra digitally as soon as possible. If a person is dead, it should be intimated to the Employees Provident Fund Organization, Regional Office, Port Blair immediately alongwith Death Certificate for further necessary action.

Online Fire Clearance Certificate Facility for N&M A & N District launched

Port Blair, Sept. 21

The A & N Fire Service is presently providing online facility for issuance of Fire Clearance Certificate through online Portal (http://andssw1.and.nic.in/swc/depts/fire and http://andssw1.and.nic.in/ospfire) for Port Blair Tehsil of South Andaman only. To improve ease of doing business, on the initiative of Shri Neeraj Thakur, DGP, A & N Islands, facility of online Fire Clearance Certificate (FCC) through Single Window System has now been extended to N & M Andaman and Nicobar District as well. The entire project has been completed in collaboration within NIC, Port Blair.

The online FCC will

contd. at page-5

संपादकीय

खेल और खिलवाड़

युवाओं में खेल–कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकारें अनेक योजनाएं चलाती हैं। मकसद है कि क्षेत्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगताओं के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हर जिले में खेल अधिकारी नियुक्त हैं, जो खिलाड़ियों के कौशल को निखारने की जिम्मेदारी निभाते हैं।

मगर हमारे देश में सरकारी योजनाएं किस तरह भ्रष्टाचार और कदाचार का शिकार हो जाती हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही योजनाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए तैयार भोजन को शौचालय में रखने की घटना है। जब उस घटना का वीडियो बड़े पैमाने पर प्रसारित हो गया, तब प्रशासन की नींद खुली और खुद जिलाधिकारी ने घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपी।

सरकार ने तत्काल संबंधित अधिकारी को निलंबित और भोजन की व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मगर इस घटना और सरकार की सख्ती से दूसरे जिला खेल अधिकारियों ने कितना सबक सीखा होगा, कहना मुश्किल है।

खेल के नाम पर खेल संघों, स्टेडियमों, खेल प्रशिक्षण केंद्रों आदि में खिलाड़ियों की सुविधाओं का कितना ध्यान रखा जाता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि समय–समय पर भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षकों के बर्ताव आदि को लेकर शिकायतें आम हैं। दरअसल, ज्यादातर जगहों पर खिलाड़ियों को भोजन उपलब्ध कराने का काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है।

खासकर जब खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, तो भोजन की व्यवस्था ठेकेदार ही करते हैं। यह छिपी बात नहीं है कि ठेका देने में किस तरह कमीशनखोरी शामिल होती है। जाहिर है, इस तरह ठेकेदार भोजन की गुणवत्ता गिरा कर अपनी कमाई बढ़ाने का प्रयास करते हैं। घटिया आहार उपलब्ध कराते हैं। कम से कम कारीगरों से काम चलाना चाहते हैं। सहारनपुर वाले मामले में भी यही हुआ।

तीन सौ खिलाड़ियों के लिए भोजन तैयार करने को मात्र दो कारीगर रखे गए थे। हद तो यह कि तैयार भोजन शौचालय में रखवाया गया, जहां से लेकर खिलाड़ियों को खाना था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भोजन रखने में साफ–सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसे तैयार करने में कितना ध्यान दिया जाता होगा।

सहारनपुर की घटना से एक बार फिर यह उजागर हुआ है कि खेलों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी निभाने वाले खुद किस तरह का खेल करते हैं और उनके मन में खिलाड़ियों के प्रति कितना सम्मान है। जब वे खिलाड़ियों को ठीक से भोजन नहीं करा सकते, उनके खानपान में साफ–सफाई का ध्यान नहीं रख सकते, तो भला उनके मन में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का संकल्प कितना दृढ़ होगा।

ऐसा नहीं माना जा सकता कि खेल अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि खिलाड़ियों के जीवन में आहार की क्या अहमियत होती है, खराब गुणवत्ता और दूषित भोजन से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। मगर उन्हें योजना के पैसे में हेराफेरी और खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा का भाव इस तकाजे पर कभी गंभीरता से सोचने का अवसर ही नहीं देता। खिलाड़ियों की सेहत और प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर सख्त नजर बहुत जरूरी है।

DISCLAIMER

Readers are requested to verify and make appropriate enquiries to satisfy themselves about the veracity of an advertisement before responding to any advertisement.

The Publisher of this newspaper does not vouch for the authenticity of any advertisement or advertiser or for any of the advertisers products and services.

The Owner, Publisher, Printer, Employees of this newspaper shall not be held responsible/ liable in any manner whatsoever for any claims and/ or damages/ consequences for advertisements in this newspaper.

प्रधानमंत्री शुक्रवार को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के एकता नगर में आयोजित होने वाले विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, मोदी इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना को आगे ले जाते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण का उन्मूलन और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरन्मेंट (लाइफ) को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौती का प्रभावी मुकाबला करने की राज्यों की कार्य योजनाओं जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

बयान में कहा गया कि सम्मेलन में अवक्रमित भूमि की बहाली और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ ही वन क्षेत्र बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तेईस और 24 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह विषयगत सत्र होंगे। इनमें लाइफ, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, पर्यावरण परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की निकासी सुविधा से जुड़ी परिवेश योजना, वन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम, वन्यजीव प्रबंधन और प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

नई दिल्ली, सितम्बर 20। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इस फैसले से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती और रोजगार सर्जन में सहायता मिलेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। श्री ठाकुर ने कहा कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी विनिर्माताओं का चयन किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत सोलर पीवी मॉड्यूल की प्रतिवर्ष लगभग 65 हजार मेगावाट विनिर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष और करीब आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम में संशोधन को भी मंजूरी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि टैक्नोलॉजी नोड में सेमीकंडक्टर फैब, कम्पाउण्ड सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए पचास प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी स्वीकृति दी। इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉजिस्टिक लागत को कम करने, देश में माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जारी किया था।

इस नीति का देश के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करने और वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करने का लक्ष्य है।

शपथ पत्र

इस विलेख द्वारा मैं, अधोहस्ताक्षरी पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीस्वामी (नया नाम) जिसे पहले पी. बाग्यराज कहा जाता था, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीसामी (पुराना नाम), निजी कर्मचारी (पेशा या व्यवसाय देना) और निवासी शोर प्वाइंट गांव, बम्बूफ्लैट, फरारगंज तहसील के तहत, दक्षिण अंडमान जिला (पता) सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ।

1. कि मेरे और मेरी पत्नी और बच्चों के लिए और उनकी ओर से और प्रेषक ने मेरे पूर्व नाम पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीसामी और उसके स्थान पर मेरे पूर्व नाम / उपनाम के उपयोग को पूरी तरह से त्याग / त्याग दिया और छोड़ दिया। मैं एतद्द्वारा इस तिथि से नाम/उपनाम पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीस्वामी का नाम ग्रहण करता हूँ और इसलिए कि मुझे और मेरी पत्नी, बच्चों और प्रेषक मुद्दे को इसके बाद मेरे पूर्व नाम/उपनाम से नहीं, जाना और प्रतिष्ठित किया जा सकता है, लेकिन अब से मुझे पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीस्वामी नाम/उपनाम जाना जायेगा जोकि मैंने ग्रहण किया है।
2. कि इस तरह के अपने दृढ़ संकल्प को प्रमाणित करने के उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूं कि मैं इसके बाद सभी अभिलेखों, कार्यों और लेखों में और सभी कार्यवाही, लेनदेन और लेनदेन में, निजी के साथ–साथ सभी अवसरों मेरे पूर्व नाम/उपनाम के स्थान पर पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीस्वामी नाम/उपनाम का उपयोग और हस्ताक्षर करूंगा।
3. कि मैं स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता हूँ और सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों और विशेष रूप से रिश्तेदारों और दोस्तो से अनुरोध करता हूँ कि वे मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, प्रेषक मुद्दे को पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीस्वामी के नाम से नामित और संबोधित करें ।
4. कि जिसके समक्ष मैंने अपने पूर्व और दत्तक नाम/उपनाम पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीसामी और प्रत्यय पी. बाग्यराज, पुत्र अलगियामनवलम कुप्पुस्वामी पलानीस्वामी को उल्लेखित किया है, मेरे हस्ताक्षर और मुहर, यदि कोई हो, यह 21 सितंबर, 2022 का दिन।

साक्षी

नोटः 21/09/2022 को नोटराइज्ड अंग्रेजी शपथ पत्र का हिन्दी में अनुवादित शपथ पत्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की, रतन टाटा और सुधामूर्ति सहित नवनियुक्त न्यासी बैठक में शामिल हुए

एआईआरएन, नई दिल्ली, सितम्बर 21। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पीएम केयर्स फण्ड के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम केयर्स फण्ड द्वारा चार हजार 345 बच्चों की मदद कर रही पीएम केयर्स योजना और इस कोष के विभिन्न प्रयासों के बारे चर्चा की गई। ट्रस्टियों ने देश में कठिन समय में इस कोष की उल्लेखनीय भूमिका की सराहना की। श्री मोदी ने पीएम केयर्स फण्ड को पूरे मन से समर्थन देने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया।

चर्चा में कहा गया कि पीएम केयर्स आपात स्थिति में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके लिए राहत सहायता देने के साथ ही पीएम केयर्स रोकथाम और क्षमता बनाने के उपाय भी करता है। प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों के पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने का स्वागत किया।

बैठक में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों, केन्द्रीय गश्हमंत्री और केन्द्रीय वित्तमंत्री ने भी भाग लिया। फंड के नवनियुक्त ट्रस्टियों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के. टी. थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा संस के चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा ने भी बैठक में भाग लिया।

ट्रस्ट ने यह फैसला भी किया कि पीएम केयर्स फंड के परामर्श बोर्ड में जानी–मानी हस्तियों को शामिल किया जायेगा। इनमें भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखाकार राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधामुर्ति और टेक फॉर इंडिया के सहसंस्थापक इंडिकॉरर्स तथा पीरामल पाउंडेशन के पूर्व सी.ई.ओ. आनंदशाह शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि नये ट्रस्टियों और सलाहकारों के शामिल होने से पीएम केयर्स फंड के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन लोगों के व्यापक अनुभव से लोगों की जरूरतें पूरी करने के काम में और तेजी आएगी।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कथन कि यह समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही है

एआईआरएन, नई दिल्ली, सितम्बर 21। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कथन कि यह समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही है। श्री मैक्रों ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उजबेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में कहा था कि वर्तमान दौर युद्ध के लिए नहीं है।

इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वे यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत की स्थिति से अवगत हैं और जितनी जल्दी हो सके युद्ध समाप्त करना चाहते हैं।

अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने भी कहा कि अमरीका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन का स्वागत करता है।

वित्त मंत्री सीतारामन ने वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों से कहा कि हरित वित्त के क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट अवसरों का लाभ उठायें

एआईआरएन, नई दिल्ली, सितम्बर 21। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों से आग्रह किया है कि हरित वित्त के क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट अवसरों का लाभ उठायें और सतत वित्तीय माहौल तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने वित्तीय कारोबारी कंपनियों से कहा कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव रखें। ग्लोबल फिनटेक फैस्ट को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान और किसी भी नीतिगत मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा मौजूद हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनका बैंक वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों के नवाचार को सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी।

डॉ. एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोलु से मुलाकात की

एआईआरएन, नई दिल्ली, सितम्बर 21। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के बीच तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोलु से मुलाकात की। ट्वीट संदेश में, डॉ. जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, जी–20, वैश्विक व्यवस्था, नैम और साइप्रस जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री ने आज न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय क्षेत्रीय समूह की मेजबानी करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और विश्व के दक्षिणी देशों पर इसके प्रभावों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में जी–20 के महत्व का भी जिक्र हुआ।

गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित

एआईआरएन, नई दिल्ली, सितम्बर 21।

गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए इसकी घोषणा की। छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। यह फिल्म 14 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

छेल्लो शो का शीर्षक अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म का रॉबर्ट डे नीरो के ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उद्घाटन फिल्म के रूप में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था और इसने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं।

छेल्लो शो के निर्देशक नलिन पैन ने ऑस्कर के लिए फिल्म का चयन करने पर फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और जूरी सदस्यों को धन्यवाद दिया है।

छेल्लो शो एक किशोर बालक की कहानी है। वह भारत के एक दूरदराज के गाँव में रहता है और सिनेमा के साथ उसका गहरा संबंध जुड जाता है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ से फिल्में देखने में पूरी गर्मियों का समय बिताता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई दायरे-पीसीएएफ से हटाया

एआईआरएन, नई दिल्ली, सितम्बर 21। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई दायरे– पीसीएएफ से हटा दिया है। विभिन्न वित्तीय अनुपातों तथा कर्ज वसूली में विफलता से जुड़ी बैंक की गतिविधियों में सुधार को देखते हुए यह फैसला किया गया है। जब भी कोई बैंक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर पीसीएएफ लागू किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर कर्जों की वसूली न कर पाने और परिसंपत्तियों से नकारात्मक अर्जन के कारण 2017 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीएएफ सूची में शामिल किया था। अब बैंक के कामकाज की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने ये प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लिखित रूप से प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह सभी नियमों का अनुपालन करेगा।

A&N Islands declared as '1st Swachh Sujal Pradesh' in the country; Hon'ble Jal Shakti Minister presents the award to Hon'ble Lt. Governor

Port Blair, Sept. 17

The Andaman & Nicobar Islands has been declared the '1st Swachh Sujal Pradesh' in the entire country by the Hon'ble Jal Shakti Minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat during a felicitation programme held at DBRAIT Auditorium this evening. Presenting the award to the Hon'ble Lt. Governor, A&N Islands & Vice Chairman, Islands Development Agency, Admiral DK Joshi, PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.), the Minister congratulated the Lt. Governor, the entire team of A&N Administration, PBMC, PRIs, Political party representatives and the general public of A&N Islands in fulfilling the dream of the Prime Minister in achieving saturation in the implementation of his mission to make India a 'Swacch Bharat'.

Shri Gajendra Singh Shekhawat while addressing the gathering remarked that A&N Islands presented the most precious gift to the Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi on his 72nd birthday today, befitting the occasion by fulfilling his Mission of 'Swacch Bharat' and 'Har Ghar Jal' by being declared as 1st Swachh Sujal Pradesh' in the entire country. "I feel proud to be on this holy soil to declare A&N Islands as 1st Swachh Sujal Pradesh", the Minister said.

The Minister stated that A&N Islands' played a pivotal role in the freedom struggle of the country. The Islands bear testimony to the inhumane treatment meted out to the freedom fighters, who fought valiantly and dreamed of a country where every Indian has access to their basic necessities. This occasion also reminds us to introspect ourselves and the responsibility to serve our countrymen with their basic needs, has been fulfilled or is yet to be fulfilled.

Highlighting the success of Jal Jeevan Mission, the Minister eulogized the efforts and vigour with which the Prime Minister delivers his promises and the driving force which has transformed this mission into a 'Jan Andolan'. Under the mission, 7 crore people have been provided individual tap connection within a span of three years which, he said, is a massive achievement.

The Prime Minister's vision of an 'Atma Nirbhar Bharat' can only be achieved with the concerted effort of each citizen in fulfilling the missions he initiated, said the Minister. He further said that India became the world's fifth-largest economy from 10th position since the Narendra Modi Govt. came to power in the year 2014. The Govt. is working on mission mode to make India a developed country by 2047 when it celebrates its centenary year. The Minister exclaimed with pride that the world is acknowledging the progress India is making at global level and how it has set the tone to become a role model for other countries.

Lauding the Islands' scenic beauty, the Minister said, A&N Islands bestowed with nature's bounty is a sight to behold; we must continue to ensure its upkeep. India has shown the world its determination in setting targets and achieving it, he said.

Speaking on the occasion, the Lt Governor, A &N Islands, Admiral DK Joshi stated that in 75 years history, it is for the first time, that a Cabinet Minister along with Secretary and senior officials from the Ministry of GoI has visited the territory to celebrate an achievement which is creditable. The Lt. Governor said, 'Har Ghar Jal' and ODF+, both these mission have achieved 100 % compliance, which is a landmark achievement considering the Islands' topography and its scattered nature, having an area of around 8249 sq.km, which is quite large when compared to many States in the mainland India. This achievement speaks volume of the service delivery system of the Administration starting from the northern most part of the Island to the southernmost, covering the Islands length and breadth, the Lt Governor remarked.

The achievement made in ODF+ (Grameen) is appreciable. In A&N Islands, there is only one urban sector i.e. Port Blair Municipal Council while the rest comes under the rural sector. In urban sector, ODF++ target was achieved in 2021, said the Lt. Governor adding that under the dynamic leadership of Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi and with the sincere effort of Administration and support of general public 'Swachh Bharat Mission (Gramin) and Jal Jeevan Mission Yojana has been successfully implemented in these Islands. For A&N Islands to be declared as '1st Swachh Sujal Pradesh', the Ministry has carried out a comprehensive verification during which all important parameters viz. quality of water, quantity of water supply, regularity of water supply were thoroughly verified, after which only, the Ministry gave the Certificate.

The Lt. Governor further stated that on March, 22, 2021 FSTC (Functional Household Tap Connection) facility has been made available in all the villages and on September 15, 2022, 100% Har Ghar Jal certifications have been achieved through the support of Gram Sabhas. The Lt Governor congratulated the concerned Departments for achieving this success.

The Lt. Governor said that taking forward the people oriented welfare schemes/policies and with the support of the Govt. of India, under the aegis of Islands Development Agency, projects worth of around Rs. 88,765 crores have been implemented towards infrastructure development and improvement in connectivity. The Lt. Governor pointed out that under IDA, out of the 44 projects, CANI Submarine OFC Project, Azad Hind Fauj Setu at Humphry Strait and 20 MW Solar Power projects like 13 (30%) important projects have been completed and remaining 27 (61%) projects are under different stages of development. The Lt. Governor further said that A&N Administration is committed towards taking these Islands on the path of progress as also developing a new India of the 21st Century during this 'Amrit Kaal'.

In her address, the Secretary, Jal Jeevan Mission, GOI, Ms Vini Mahajan, IAS congratulated the A&N Islands for achieving this feat of becoming the 1st Swachh Sujal Pradesh in the entire country, which she said is a very big achievement. She remarked that this achievement should not stop the Islands from continuing the Mission and it should strive to continuously ensure provision for availability of safe water and cleanliness to the Islanders. She remarked that for the mission to be successful, it requires peoples' participation from the highest to the grass root level. She said proper sanitation, safe & clean water, hygienic environment needs to be maintained.

Speaking on the occasion, the Chief Secretary , A&N Administration, Shri Keshav Chandra, IAS said, it is indeed a proud moment for all of us today that the UT of Andaman and Nicobar Islands is being declared 'Swachh and Sujal Dweep Samooh' by the Hon'ble Minister. The achievements stands testimony to the concerted efforts made by the Departments in implementation of the schemes in these remote archipelago. Under Swachh Bharat Mission (Grameen), universal sanitation coverage is achieved with the construction of Individual Household Latrines and Community Sanitary Complexes. With the GoI's vision of "No One Left Behind" for sanitation access, the UT has additionally provided Indivdual Household Latrines (IHHLs) to 3828 individuals which are completed in full shape. Further, 296 Community Sanitary Complexes under SBM(G) Phase-I and 39 CSCs sanctioned under SBM(G) Phase-II have also been completed, the Chief Secretary mentioned .

The Chief Secretary stated that the Islands have set-up mechanism for Solid and Liquid Waste Management. The waste generated are segregated, bailed and sent for onward recycling. Inspite of the conveyance challenges, the waste are transported from inter-islands to Port Blair and from Port Blair to Mainland. Collaboration has been made with approved recyclers and Gram Panchayats are earning income by selling of waste. An amount of Rs. 21,55,881/- has been earned by the Gram Panchayats by selling of dry waste to recycler. He further stated that for effective Solid Waste Management, the Department has sanctioned 26 Solid Waste Management (SWM) clusters covering 70 Gram Panchayats in the Islands, out of which 24 are ready and functional. The SWM cluster site has provisions for treatment of organic waste by means of Composting. The SWM Clusters have also been equipped with Bailing and Shredding machine for processing of non-biodegradable Solid Waste. Considering the saturation of IHHLs and CSCs, efforts were made to augment the existing infrastructure arrangements available with the Gram Panchayat for carrying out Solid Waste Management activities as per the Solid Waste Management Rules, 2016 and the UT specific Andaman and Nicobar Islands (Rural Areas) Solid Waste Management and Handling Bye Laws, 2019, the Chief Secretary remarked.

Earlier, in her welcome address, Commissioner-cum-Secretary (RD/Panchayat & PRI), A&N Administration, Ms. Nandini Paliwal, IAS said that it is a proud moment for the people of A&N Islands Andamans to have the Hon'ble Minister amongst us on this auspicious occasion for declaring the UT of Andaman & Nicobar Islands as 'First Swachh Sujal Pradesh'. The Union Territory of A&N Islands has achieved ODF Plus status for all its villages and has been declared as first ODF plus UT of the country. The UT Administration has been committed towards providing universal sanitation coverage in rural areas of the Island. In order to have effective Solid Liquid Waste management, the UT has taken measures to set-up 26 Solid Waste Management Clusters which would cater to entire 70 Gram Panchayats of Andaman, she said.

contd. at page-5

Admn committed towards... *from page 1*

filled overnight. The Heads of critical service Departments like Education, Health, Electricity, APWD were advised to work out some immediate solution to fill the gaps in remote part of the Islands and also to take strict action against the under performing Govt. servants and those reluctant to join or work in remote part of the islands. The PRIs were also advised to remotely monitor and inform the Heads of Departments in case any Govt. servant posted in their area fails to render desired services.

On the issue of scarcity of drinking water during dry spell to meet the ever increasing demand, the Chief Secretary instructed the concerned officials and PRIs to identify more water bodies/water sources to find a permanent solution. He further directed the officials of APWD to prepare detailed action plan and priority list in consultation with the PRIs.

Regarding the issue of poor road condition, the Chief Secretary informed that the NHIDCL officials have assured that they will complete the critical stretch between Sitanagar and Kalara Jn. within two months time. He further informed that the works taken up under PMGSY have now been transferred to APWD and the PRI members will be intimated as soon as the road work is sanctioned for their respective Panchayats. On the issue of shortage of LPG Cylinders, the Chief Secretary said that the Administration will resolve the issue and efforts are also on to increase the capacity of the LPG Bottling Plant for a permanent solution.

Inspecting the Karmatang Beach area where two eco-friendly resorts are to be developed under the aegis of NITI Aayog, the Chief Secretary said, this will boost up economy and generate ample employment opportunity for local youth of the area. At SLWM cluster site at Rampur, the Chief Secretary directed the DC N&M to prepare a SOP for disposal of garbage in a systematic manner to maintain better sanitation in the area.

The Chief Secretary also visited Govt. Senior Secondary School Karmatang-10 and lauded the exemplary efforts of the Principal and teachers. He advised all PRI members and officers to visit the school to see for themselves the way the school is beautified and maintained.

Thereafter, the Chief Secretary visited Mahatma Gandhi Govt. College, Mayabunder and garlanded the statue of the Father of the Nation Mahatama Gandhi. He also witnessed a cultural programme in the College auditorium. While addressing the students, the Chief Secretary urged them to live a disciplined life and contribute to the society after completion of their studies. A&N Islands will have its own University very soon, the Chief Secretary disclosed. He further stated that A&N Administration is following up the matter with UGC. He also praised the entire College fraternity and students for keeping the college premise spic & span.

This was followed by visit to the Dr RP Hospital Mayabunder during which the Chief Secretary interacted with the doctors and medical staff. He also visited the under construction Multi Purpose Hall at Mayabunder and directed the officials to speed up the work by increasing the manpower and strive to complete the work by December, 2022.

Later in the afternoon, the Chief Secretary visited the STS workshop and enquired about the availability of spare parts for taking up repair works. He also instructed for installing GPS in buses for better tracking and timely availability of bus service to commuters. He inspected the Power Plant at Panighat established by a Pvt. Power generator firm from whom the Electricity Department is purchasing power on per Unit Cost basis. The Chief Secretary also visited PHC Tugapur where he instructed the authorities to take up renovation of the PHC and create a better ambience.

The Chief Secretary also visited vegetable Garden developed under MGNREGA at Gram Panchayat Chainpur and appreciated the efforts of the Gram Panchayat for growing vegetables to achieve self sufficiency in food security.

Online Fire Clearance.... *from page 1*

enable the business community to apply Fire Clearance from anywhere, track the status of their application and receipt of FCC in a time bound manner without any physical visit. Henceforth, all Govt./ private enterprises have been advised to submit their application/ request for seeking Fire Clearance Certificate (FCC) online, a press release from SP(Fire) said.

Advt ID: 9072, 2022/MediaRelease/703

Training on Waste Management in Agri. & Allied Sector gets underway

Port Blair, Sept. 20

The Secretary (Agri), A&N Administration, Shri Pankaj Kumar, IAS inaugurated a four days off Campus training programme on 'Waste Management in Agri.& Allied Sectors' for the officers of Agriculture and allied Departments of A&N Islands today in the Conference Hall of Directorate of Agriculture, Haddo. The programme is being organized by Extension Education Institute, PJTSU, Hyderabad in association with Department of Agriculture, A&N Administration. Speaking on the occasion, the Secretary (Agri.) motivated the participants to participate actively and acquire the scientific knowledge through agricultural waste management training programme, for its effective implementation in the field. Since agriculture is on a large scale, the agricultural wastes generated cannot be ignored and proper care has to be taken to decompose it through the agricultural waste management programme.

The Joint Director (Agri.), HQ, Dr (Smti) Chanda Srivastava stressed upon the need of such training for extension functionaries of scheme implementing Departments while Dr I. Sreenivasa Rao, Senior Professor, EEI briefed about the course contents of the training & insisted for transfer of knowledge & skills learned for the benefit of farming community. Dr. R. Vasantha, Professor, EEI proposed the vote of thanks.

Altogether, 30 officers from Agriculture & Allied Departments i.e. Department of Animal Husbandry & Veterinary Services, Fisheries and Rural Development are participating in the training programme, a press release from Directorate of Agriculture said.

A&N Islands... from page 4

The programme which was attended among others by the Member of Parliament, Shri Kuldeep Rai Sharma, Adhyaksha, ZPSA, Smti Pramila Kumari, Chairperson, PBMC, Smti U. Kavitha, Senior officers of A&N Administration, PRI members and general public concluded with the vote of thanks proposed by the Secretary (RD/PRIs), A&N Administration, Shri Suneel Anchipaka, IAS.

A video on implementation of Swachh Bhrat Mission (ODF+) and Jal Shakti Abhiyan in A&N Islands were also screened on the occasion.

Earlier, the Union Jal Shakti Minister arrived to a warm welcome. He was received at the airport by the Chief Secretary, A&N Administration, Shri Keshav Chandra, IAS, senior officers from A&N Administration, representative from political parties and PRI members. Soon after arrival, the Minister visited Calicut Gram Panchayat, where he inspected the Amrit Sarovar, IHHL site, compositing of organic wastes, 'Green House' created in the farm of P. Pachaimuthu, a beneficiary of the GoI schemes. While interacting with the beneficiary, the Minister enquired about his well being and asked him whether he was able to enhance his income availing these schemes. The beneficiary informed the Minister that he has received good support from the concerned Departments through which he not only increased farm activities but also earning handsomely.

Thereafter, the Minister visited the Solid Waste Management Cluster at Beodnabad and saw for himself its functioning. The PRI members informed the Minister that solid waste management is being effectively implemented in their Panchayat which has not only helped them to keep their Panchayats Swatchch but it has also generated employment to the residents of the area.

Later in the evening, the Minister also visited the National Memorial Cellular Jail.

Environment Ministry's Panel shows green flag for project worth Rs.72,622 crores for holistic development of Great Nicobar Island

Port Blair, Sept. 17

The prestigious project of holistic development of Great Nicobar Island (GNI) will transform the Island into a hub of port led development. The GNI project has been conceived based on the principles of Sustainable Development wherein the ecological, economic and social factors have been given due consideration at every stage. Considering the national importance of the project in view of the security, socio economic benefit and strategic location of transhipment terminal, the Govt. of India has conceived the project at an estimated cost of Rs. 72,622 crores after careful consideration of environmental status of Great Nicobar Island.

A report by Economic Times (ET) and Business Standard (BS) stated that the Environment Ministry's panel has cleared project to construct a Greenfield International Airport, an International Container Transhipment Terminal, a Township and Power plant in Great Nicobar Island. The Expert Appraisal Committee (EAC) consisting of few government officials, mostly subject experts and eminent scientists from various fields of Environment, Pollution control, Ground water, Road research, ocean technology, infrastructure, Power amongst others, after extensive rounds of deliberations and meetings recommended grant of Environmental and Coastal Regulation Zone (CRZ) Clearance for the project in its meeting held on 22.08.2022 – 23.08.2022. A series of meetings and deliberations including for Terms of Reference (ToR) for Environmental Impact Assessment (EIA) and EAC were held from March 2021 and finally concluded in August 2022 before the recommendation for grant of Environmental and CRZ clearance by the EAC for GNI project.

The ET and BS report further said, "The Indian Ocean Region (IOR) in general and the Indian Ocean in particular has turned into a strategic hotspot in recent years. In response to the increasing strategic value of this IOR, a critical mass of development in the Andaman and Nicobar Islands is necessary for strengthening India's regional presence". The Great Nicobar Island also represents a significant economic development opportunity as the main east-west shipping route that links East Asian exports with the Indian Ocean, Suez Canal and Europe runs just to the south of this Island, it said. "By building a container port in this location, India can participate more fully in the global shipping trade" and generate lakhs of new job, the report said. Other countries like Mayanmar, China and Sri Lanka were gearing upto develop deep water facilities for taking a major share of trade by developing suitable harbour facilities and it is therefore imperative that India should do the same, the report contended. Great Nicobar Island is considered perfect as a site as it is equidistant from Colombo, Port Klang and Singapore and is also very close to the East-West International corridor.

Out of 910 sq. km of Great Nicobar Island, only 166.10 sq. km of area is proposed for development which is approximately 18% of the total area. Remaining area of 82% will stay covered under Protected Forest, two National Parks, Eco Sensitive Zones and Biosphere Reserve and managed for conservation of biodiversity at ecosystem, species and genetic levels. The total forest area to be diverted out of 166.10 Sq. Km. including deemed forest is 130.75 Sq. Km. Remaining project area of 35.35 Sq. Km. lies in the Revenue area. About.50 % of the total forest area to be diverted forming 65.99 Sq. Km. will be reserved as green area and no tree felling is envisaged here.

In the remaining forest area to be diverted, felling of trees is proposed in a phased manner over a period of 30 years. Further, Compensatory Afforestation is proposed to be carried out as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) for diversion of forest land.

ET report further said, " EAC has mandated specific conservation and management plan and high funding for the endemic species, Mangroves and Coral and other fauna besides several other caveats". EAC said three independent committees will be set up: one to oversee pollution related matters, another on biodiversity and the third to oversee welfare and issues related to Shopmen and Nicobarese tribes. Accordingly, an EIA has been undertaken for preparation of conservation and management plan to have minimal environmental and social impact due to the project. The exhaustive Environmental Management plan will be put in place and monitored on a regular basis. Accordingly, Wildlife Institute of India (WII), Salim Ali Centre for Ornithology & Natural History (SACON), Zoological Survey of India (ZSI), Botanical Survey of India (BSI) have been entrusted byA & N Administration for preparation of conservation/mitigation plans for bio-diversity including leatherback turtles, megapode, crocodile, etc. Conservation and protection of Nicobar macaque, robber crabs, endemic birds, mangroves, giant clamsand other endemic flora and fauna have been given due consideration. Additionally, the UT Administration is in the process of notification of three Wildlife Sanctuaries for Leatherback Turtles in Little Nicobar (13.75 sq.km), Megapode in Menchal (1.29 sq.km) and Corals in Meroe Island (2.73 sq.km), for conservation of these species.

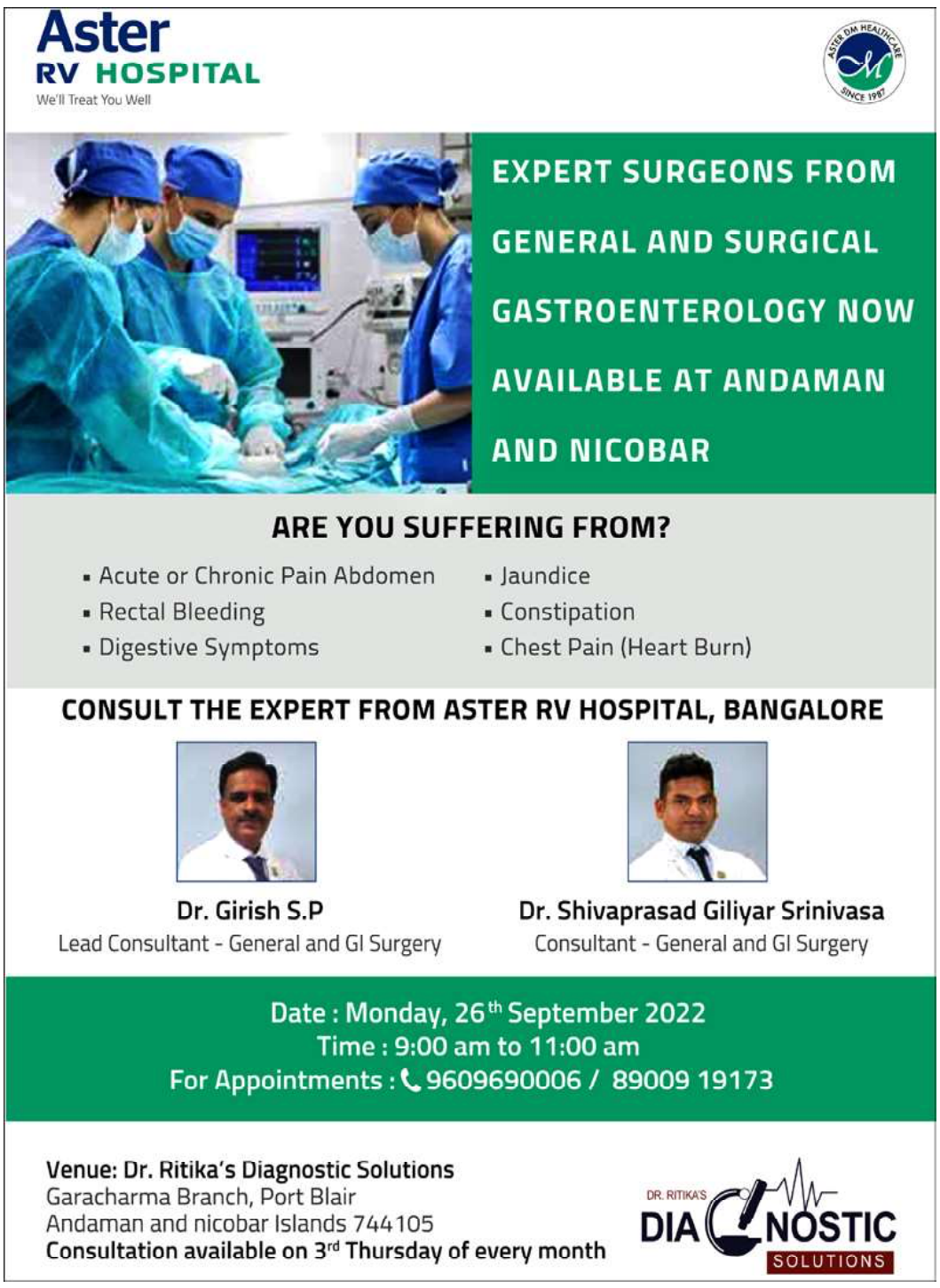

DC (SA) holds...

from page-1

held a meeting with all the stakeholders for retails sale of crackers.

The representatives of Andaman and Nicobar Chamber of Commerce and Industries have been directed to coordinate and submit the list of shopkeepers willing for allotment of temporary stalls. As per space availability and past precedence, it was decided that 50 stalls at ITF ground and 20 stalls at Bathubasti area may be allowed to operate on receipt of fire clearance certificate from Fire Service Department.

The sale of crackers will be done from ITF Stall and Bathubasti area from 20.10.2022 to 22.10.2022 and from 23.10.2022 to 24.10.2022 between 1000 hrs to 2100 hrs.

The Deputy Commissioner, South Andaman further advised the dealer community to ensure and promote the storage and sale of green fire crackers as per the National Green Tribunal (NGT) guidelines and advised for strict adherence of the licencing capacity for storage of fire crackers and to prevent illegal/unauthorized import and sale of foreign origin fireworks during the festive season and also to prevent import and sale of banned fireworks. On receipt of reports regarding any deviation strict action shall be initiated against them under the Explosive Rules, 2008.

Editor, Owner & Publisher: Reshu Shanker **at** Sakshee Printer & Publishers, Opp Chinmaya Mission, Police Line Road, P.O: Shadipur, Port Blair, South Andaman- 744106 and Published at MB-22, Aberdeen Village, Port Blair, District- South Andaman, A&N Islands, Pin-744104,
Editor: **Reshu Shanker,** Cell No: 9476014043, 03192-235327, Email:transitionerapb@gmail.com